Now, with regard to the point as to what action we have taken, Sir, I would like to again repeat that as soon as such complaints are received, we immediately refer them to the concerned Embassies. Then we write a letter to the Chief Ministers concerned. Then follows the prosecution proceedings on the woman's complaint. So, on the one side, there is the provision of prosecution, and on the other side, we see in what way we can deal with them in the host countries in which they are living. Then, there is a proposal which has yet to take place legally. Once we become a member of the Hague Conference, the International Private Law will come into operation. On that basis, the two things, 44A of the Civil Procedure Code as well as 29C of the Civil Procedure Code would become applicable once we become a member, and then there will be a bilateral agreement with these countries.

MR. CHAIRMAN: Next question, Q. No. 243. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती विप्लव ठाकुर: सर, यह इतनी इम्पोर्टेन्ट बात है, हमें भी बोलने का टाइम दिया जाए ...**(व्यवधान)**... इतनी इम्पोर्टेन्ट बात है ...**(व्यवधान)**... हमें टाइम दिया जाए ...**(व्यवधान)**... महिलाओं को बोलने दिया जाए ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please. Q. No. 243. ...*(Interruptions)*... Q. No. 243. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, we never get a chance. Please see how many Members want to speak. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I understand the importance of the subject. But there are questions which have to be gone through. ...*(Interruptions)*... There are other procedures by which this subject can be discussed at length. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, please allow a Half-an-Hour discussion. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: The concerned Members can request for a Half-an-Hour Discussion on this subject. ...*(Interruptions)*... Q. No. 243 please. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती विप्लव ठाकुर: इसे रख लीजिए ...**(व्यवधान)**... हम कर देंगे।

'नदियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय-नीति'

†*243. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह भी सच है कि देश की अधिकांशत: बड़ी नदियों का जल प्रदूषित होकर काला पड़ चुका है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त समस्या से निपटने के लिए किये गए सारे प्रयास विफल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

†मूल सूचना हिन्दी में प्राप्त हुई।

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (घ) एक विवरण सभापटल पर रखा है।

विवरण

(क) से (ग) औद्योगिक प्रदूषण और अन्य प्रदूषण के गैर-बिन्दु स्रोतों के अलावा घरेलू प्रदूषण नदियों के प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। अशोधित सीवेज का अवरोधन और दिशापरिवर्तन और सीवेज शोधन संयंत्र लगाना नदी संरक्षण योजना में किए गए प्रदूषण निवारण कार्यों के मुख्य घटक हैं। जहां तक औद्योगिक प्रदूषण का संबंध है इस दिशा में किए गए प्रयासों में उद्योग विशिष्ट बहिस्राव मानक अधिसूचित करना, बहिस्राव शोधन संयत्रों को स्थापित करने को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत केन्द्र/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा पर्यावरण की निगरानी करना शामिल है।

गंगा कार्य योजना में दोनों चरणों के अंतर्गत अब तक पूरे हो चुके प्रदूषण निवारण कार्यों से अब गंगा नदी की जल गुणता में गंगा कार्य योजना से पूर्व की गुणता की तुलना में, मुख्य स्थलों पर, सुधार दिखाई दिया है। यमुना नदी के संबंध में, नदी जल गुणता में, विशेष रूप से दिल्ली में सीवेज शोधन क्षमता की मांग और उपलब्धता के बीच भारी अंतर होने के कारण और नदी में न्यूनतम प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता की कमी के कारण अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। अन्य नदियों के संबंध में कार्य पूरा होने के विभिन्न चरणों में है।

जनसंख्या में वृद्धि के कारण, निरंतर बढ़ते प्रदूषण भार के साथ नदी संरक्षण एक सक्रिय कार्य है। संरक्षण नीति की कार्यनीतियों की पुनरीक्षा और अन्य शहरों और नदियों की पहचान करना एक सतत प्रक्रिया है। जल राज्य का विषय होने के कारण नदियों में प्रवाहित होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए उचित सीवरेज अवसंरचना का सृजन करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार पहचान किए गए प्रदूषित स्थलों के लिए पूंजीगत कार्य करने के लिए केवल एकमुश्त अनुदान प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करती है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना सरकार का एक मुख्य कार्यक्रम है।

(घ) प्रदूषण निवारण कार्यों की अनुमोदित लागत, किया गया व्यय और सृजित सीवेज शोधन क्षमता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत किया गया राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

क्र. स.	राज्य	अनुमोदित लागत	किया गया व्यय#	सृजित सीवेज शोधन संयंत्र की क्षमता (एमएलडी)
1	2	3	4	5
क	**गंगा कार्य योजना चरण-I**			
1	उत्तर प्रदेश	199.95	194.46	375.09

1	2	3	4	5
2	बिहार	57.29	52.73	122.50
3	पश्चिम बंगाल	188.05	186.13	371.60
	उप योग :	445.29	433.32	869.19
	स्थापना और अनुसंधान एवं विकास	16.75		
	कुल (जीएपी-I) :	462.04	433.32	869.19
ख	**राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना**			
1	आंध्र प्रदेश	395.11	133.87	24.46
2	बिहार	32.42	2.98	0.00
3	दिल्ली	573.73	160.70	30.00
4	गुजरात	93.83	95.08	232.00
5	गोवा	14.10	10.92	12.50
6	हरियाणा	311.06	253.92	322.00
7	झारखंड	41.34	1.46	0.00
8	कर्नाटक	72.00	52.32	40.27
9	केरल	18.45	0.00	0.00
10	मध्य प्रदेश	101.19	68.52	144.41
11	महाराष्ट्र	123.17	100.94	155.00
12	उड़ीसा	72.27	37.59	33.00
13	पंजाब	234.58	242.08	141.20
14	राजस्थान	13.21	0.77	0.00
15	तमिलनाडु	1103.10	734.24	394.36
16	उत्तरांचल	85.64	16.63	4.18
17	उत्तर प्रदेश	924.43	472.26	445.81
18	सिक्किम	15.81	8.13	0.00
19	पश्चिम बंगाल	394.65	155.40	75.85
20	नागालैंड	31.74	0.00	0.00
	उप-योग :	4651.85	2547.80	2055.04
	स्थापना और अनुसंधान एवं विकास	130.73		
	कुल (राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना) :	4782.58	2547.80	2055.04
	कुल योग (क+ख)	5244.62	2981.12	2924.23

--> ऊपर दिए गए व्यय में राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष खर्च न किए गए बकाया को आगे ले जाया गया भारत सरकार और राज्य सरकार के हिस्से का व्यय शामिल है।

National policy for protection of rivers

†*243. SHRI PYARELAL KHANDELWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that water of most of the major rivers has become black after getting polluted;

(b) whether it is also a fact that all efforts to deal with the said problem have proved infructuous;

(c) if so, whether Government are considering to formulate any national policy to protect rivers from getting polluted; and

(d) if not the details thereof State-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI NAMO NARAIN MEENA): (a) to (c) Domestic sewage is the major source of pollution of rivers besides industrial and other non-point sources of pollution. Interception and diversion of raw sewage and setting up of Sewage Treatment Plants have been among the main components of pollution abatement works undertaken in the River Conservation Plan. As regards pollution by industries, efforts taken include notifying industry specific effluent standards, promoting setting up of Effluent Treatment Plants and environmental surveillance by the Central/State Pollution Control Board under Environment Protection Act 1986 and Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

With the pollution abatement works completed so far in both the phases under Ganga Action Plan, the water quality of the river Ganga has shown improvement at major locations over its pre-GAP quality. In respect of river Yamuna, the quality of river water has not shown the desired improvement owing to the large gap between the demand and the availability of sewage treatment capacity particularly in Delhi, and the lack of availability of fresh water for ensuring minimum flow in the river. The works in respect of other rivers are at different stages of completion.

Conservation of rivers is a dynamic activity with the ever increasing pollution load due to increase in population. Review of the strategies of conservation policy and identification of additional towns and rivers is a continuous process. Water being a State subject, it is the responsibility of State Governments to create proper sewerage infrastructure to prevent pollution from entering the rivers. Central Government only supplements the efforts of the State Governments by providing one time grant for capital works for identified polluted stretches. The National River Conservation Plan is a major programme of the Government.

(d) A statement indicating state-wise approved cost of pollution abatement works, the expenditure incurred and the sewage treatment capacity created is given in the statement.

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

Statement

State-wise expenditure incurred under National River Conservation Plan

(Rupees in crores)

Sl. No.	STATE	Approved Cost	Expenditure Incurred#	STP Capacity Created(mld)
1	2	3	4	5
A	**GANGA ACTION PLAN PHASE-I**			
1	Uttar Pradesh	199.95	194.46	375.09
2	Bihar	57.29	52.73	122.50
3	West Bengal	188.05	186.13	371.60
	SUB TOTAL :	445.29	433.32	869.19
	Estt. and R&D	16.75		
	TOTAL (GAP-I) :	462.04	433.32	869.19
B	**NATIONAL RIVER CONSERVATION PLAN**			
1	Andhra Pradesh	395.11	133.87	24.46
2	Bihar	32.42	2.98	0.00
3	Delhi	573.73	160.70	30.00
4	Gujarat	93.83	95.08	232.00
5	Goa	14.10	10.92	12.50
6	Haryana	311.06	253.92	322.00
7	Jharkhand	41.34	1.46	0.00
8	Karnataka	72.00	52.32	40.27
9	Kerala	18.45	0.00	0.00
10	Madhya Pradesh	101.19	68.52	144.41
11	Maharashtra	123.17	100.94	155.00
12	Orissa	72.27	37.59	33.00
13	Punjab	234.58	242.08	141.20
14	Rajasthan	13.21	0.77	0.00
15	Tamil Nadu	1103.10	734.24	394.36
16	Uttranchal	85.64	16.63	4.18
17	Uttar Pradesh	924.43	472.26	445.81

1	2	3	4	5
18	Sikkim	15.81	8.13	0.00
19	West Bengal	394.65	155.40	75.85
20	Nagaland	31.74	0.00	0.00
	SUB TOTAL :	4651.85	2547.80	2055.04
	Estt. and R&D	130.73		
	TOTAL (NRCP) :	4782.58	2547.80	2055.04
	GRAND TOTAL (A+B) :	5244.62	2981.12	2924.23

--> Expenditure given above includes the balance of GOI's share carried over from the unspent balance by State Government for previous years. and expenditure from State Governments' share.

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: मान्यवर सभापति जी, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल विशेषकर नदियों और प्रदूषण के संबंध में है। हम जानते हैं कि सारी दुनिया की सभ्यता और संस्कृति नदियों के किनारे पली, बढ़ी और पनपी है। अगर हम सारे देश में देखें तो चाहे गंगा हो, यमुना हो, नर्मदा हो या अन्य कोई नदी गोदावरी या कावेरी हो, इन सब जगहों पर लोग इसलिए बसे क्योंकि उन्हें शुद्ध पानी मिलता था, रहने के लिए अच्छी वायु, अच्छा वातावरण मिलता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से या यह कहिए कि लगभग एक शताब्दी से सारे देश की नदियों में इतना प्रदूषण हो गया है कि लोगों को शुद्ध पानी भी नहीं मिलता है। आज से बीस, इक्कीस साल पहले सरकार ने घोषणा की थी, विशेषकर गंगा नदी के संबंध में कि गंगा नदी को शुद्ध करने के लिए सरकार एक व्यवस्था बना रही है और इस पर लगभग एक हजार करोड़ रुपए खर्च भी किए हैं। परन्तु इतना सब होने के बाद भी न गंगा का पानी शुद्ध हुआ है और न यमुना का पानी शुद्ध हुआ है। हम दिल्ली में जाकर देखें, तो यमुना का पानी काला पड़ा है। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के मकसद से 21 साल पहले राजीव गाँधी सरकार ने गंगा कार्य योजना शुरू की थी, जिस पर एक हजार करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है। इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, मैं वह आपको बताना चाहता हूँ। न्यायालय ने एतराज जताते हुए केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय और गंगा क्षेत्र के राज्यों को, मैं उन सब राज्यों का नाम नहीं लेता, 20 दिन के भीतर इस योजना की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कार्य योजना को प्रभावी बनाने के मकसद से प्रधान मंत्री को अध्यक्ष बनाया गया था। उच्चतम न्यायालय ने इस तरह की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि समस्या यहीं शुरू नहीं होती, क्योंकि प्रधान मंत्री के पास ऐसे कामों पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिलता ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आप सवाल पूछिए।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने नदियों के पानी को शुद्ध रखने के लिए और पर्यावरण को शुद्ध करने की दृष्टि से नदियों के किनारे जो उद्योग-

धंधे लगाए जा रहे हैं, शहरों का जो गंदा पानी नदियों में डाला जा रहा है, उसको रोकने के लिए पिछले 10 वर्ष में जो काम किया है, उसके परिणाम क्या हैं?

श्री दत्ता मेघे: सर, क्वैश्चन नं. 254 भी इसी से सम्बन्धित क्वैश्चन है।

श्रीमती माया सिंह : सर, क्वैश्चन नं. 260 भी इसी से सम्बन्धित क्वैश्चन है। आप तीनों प्रश्नों को combine कर दीजिए।

MR. CHAIRMAN: Please let the hon. Minister answer. ...*(Interruption)*...

श्री नमो नारायण मीणा : सर, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं को समझता हूँ, आदर करता हूँ। देश में बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं, जो एक, दो या तीन प्रान्तों में बहती हैं, लेकिन वे सारी देश की नदियाँ हैं। यद्यपि गंगा पाँच प्रान्तों से होकर गुजरती है, लेकिन यह सारे देश की नदी है, करोड़ों लोगों की आस्था का केन्द्र है। नदियाँ साफ रहनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारी लाइफ लाइन हैं, पीने का काम देती हैं, सिंचाई का काम देती हैं, नहाने का काम देती हैं। लेकिन पिछले कुछ अर्से से इन नदियों में, जिसे स्वास्थ्य वाली बात कहते हैं, वह बहुत stress में आ गया है। उसका कारण यह हैं कि उनसे बहुत ज्यादा पानी सिंचाई के लिया जाने लगा, पीने के लिए लिया जाने लगा। माननीय सदस्य, मैं आपसे सहमत हूँ, आपने यमुना की बात की। अब सवाल यह है कि यमुना में minimum flow ...**(व्यवधान)**... सर, मैं जवाब दे रहा हूँ ...**(व्यवधान)**... I will give the answer of entire question ...*(Interruptions)*...

श्री शरद यादव : सर, उन्होंने जो बात पूछी है, उन्हें उसका जवाब देना चाहिए ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आप इनका जवाब सुन लीजिए, उसके बाद सवाल पूछिए।

श्री नमो नारायण मीणा : सर, 1985 में स्वर्गीय राजीव गाँधी ने 462 करोड़ रुपए से Ganga Action Plan-I चालू की। उसके बाद GAP-II 1993 से प्रारम्भ किया गया और 1995 से सारी नदियों के लिए एक प्लान, National River Conservation Plan के रुप में चल रहा है। सारी नदियों की समस्या यह है कि हमारी नदियाँ जो गन्दी होती हैं, वे 70 परसेंट domestic sewage से होती हैं, 20 परसेंट industrial affluent से होती हैं और 5 परसेंट ...**(व्यवधान)**...

डा. मुरली मनोहर जोशी : सर, जो सवाल पूछा गया है, उन्हें उसका उत्तर देना चाहिए ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN : Please listen to the ...*(Interruptions)*... Please sit down and listen to the answer. ...*(Interruptions)*... Please sit down ...*(Interruptions)*...

श्री नमो नारायण मीणा : मैं सबका जवाब दे रहा हूँ। मैं गंगा के बारे में बात करता हूँ। सर, देश में ...**(व्यवधान)**... सर, इस सवाल में देश की सारी नदियों के बारे में पूछा गया है। The question is on all the rivers of the country. ...*(Interruptions)*... I have to anwer accordingly. ...*(Interruptions)*..... have to give details of the Ganga also. ...*(Interruptions)*... सर, 2001 में सी०पी०सी०बी० ने जो बताया है कि देश में 29 हजार MLD सीवेज जेनरेट होता है और देश में अभी हमारी कैपेसिटी सिर्फ 6 हजार MLD को ट्रीट करने की ही है। कहने का मतलब है कि जितना सीवेज जेनरेट हो रहा है, उसमें से 25 परसेंट को ही ट्रीट करने की कैपिसिटी हम डेवलप कर पाए हैं। हमने जो सारा स्टेटमेंट

दिया है, इसमें अभी तक लगभग 2700 करोड़ रुपए-- 2900 करोड़ रुपए की बात कही है, जिसमें स्टेट का भी कुछ शेयर है, उसमें भारत सरकार का शेयर 2700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। गंगा में अभी तक 740 करोड़ रुपए ...**(व्यवधान)**...

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : सर, मेरा सवाल यह नहीं है ...**(व्यवधान)**... मेरा बहुत सीधा सवाल था ...**(व्यवधान)**... आप उसका जवाब दिलवाइए ...**(व्यवधान)**... मैंने सीधा सवाल पूछा है ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: सुनिए ...**(व्यवधान)**... आपको दूसरा सप्लिमेंटरी भी मिल रहा है ...**(व्यवधान)**...

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : पहले का तो कुछ जवाब मिले ...**(व्यवधान)**... वे पहले क्वैश्चन का तो जवाब दें ...**(व्यवधान)**... दूसरा सप्लिमेंटरी तो बाद की बात है ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आप बैठ जाइए, प्लीज ...**(व्यवधान)**... आप बैठ जाइए और उनका जवाब सुन लीजिए ...**(व्यवधान)**... दूसरा सप्लिमेंटरी ...**(व्यवधान)**...

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : शहरों का गंदा पानी अन्दर डालने ...**(व्यवधान)**... औद्योगीकरण के गंदे पानी को मिलने से रोकने के लिए ...**(व्यवधान)**...

श्री शरद यादव : सभापति जी. ...**(व्यवधान)**...

SHRI NAMO NARAIN MEENA : I will not yield. ...*(Interruptions)*... सर, अभी तक उसमें कुल 2900 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिसमें से भारत सरकार का शेयर 2700 करोड़ रुपए है। गंगा की जो बात कही गई है, तो गंगा में अभी तक 740 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और यमुना में 700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बाकी पूरे देश की दूसरी नदियों में अभी तक 1500 करोड़ रुपए खर्च हो पाए हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : सर, मैंने बहुत सीधा-सा सवाल पूछा था कि ...**(व्यवधान)**... माननीय सभापति जी, मैंने बड़ा सीधा सवाल पूछा है ...**(व्यवधान)**... मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, please finish. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... Have you finished? ...*(Interruptions)*... Let us hear the second supplementary. ...*(Interruptions)*...

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : सर, मैंने जो सवाल पूछा था, उसका जवाब मिलना चाहिए ...**(व्यवधान)**...

SHRI NAMO NARAIN MEENA : Let me complete. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN : Please sit down. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*...

श्री नमो नारायण मीणा: सर, ...(व्यवधान)... यह स्व० राजीव गांधी ने प्रारंभ किया था ...**(व्यवधान)**... यह मत भूल जाइएगा ...**(व्यवधान)**... हमारी सरकार की प्राथमिकता में ...**(व्यवधान)**... हम इसके ऊपर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप दूसरा सप्लिमेंटरी पूछिए ...**(व्यवधान)**... Have you finished? ...*(Interruptions)*...

डा० मुरली मनोहर जोशी: सवाल का जवाब सीधा दीजिए ...**(व्यवधान)**... इधर-उधर की बात करने की जरूरत नहीं है ...**(व्यवधान)**... सीधा जवाब दीजिए ...**(व्यवधान)**... सभापति जी, ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Have you finished? ...*(Interruptions)*... Have you finished? ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... May I request all, please sit down? ...*(Interruptions)*...

डा० मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, यह बड़ा महत्वपूर्ण क्वैश्चन है ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, ...**(व्यवधान)**... प्राइम मिनिस्टर उस कमेटी के चेयरमैन हैं, वे बोलें ...**(व्यवधान)**... गंगा-यमुना की जो स्थिति है, वह बताएँ ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Would you ask your second supplementary? ...*(Interruptions)*... Would you please ask your second question? ...*(Interruptions)*... May I request Members to sit down?

डॉ० मुरली मनोहर जोशी: सीधा-सा सवाल है ...**(व्यवधान)**... उसका जवाब अभी तक नहीं आया ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Joshiji, your clleague is waiting to ask his question ...*(Interruptions)*... Let him ask the second supplementary ...*(Interruptions)*...

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: सभापति जी, मेरा पहला सवाल था कि प्रधान मंत्री जी उस बोर्ड के संरक्षक हैं, अध्यक्ष हैं। उनके होने के बाद भी गंगा का प्रदूषण, गंगा का गंदा पानी अभी तक साफ नहीं हो रहा है। ...**(व्यवधान)**... इसलिए मैं यह जानना चाह रहा था, एक। मेरा दूसरा सवाल था कि नदियों के किनारे पर जो औद्योगीकरण होता है, उसका गंदा पानी नदियों में जाता है, उसको रोकने में आप क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं? यह मेरा दूसरा सवाल था, जिसका जवाब नहीं मिला। अब मेरा दूसरा सप्लिमेंट्री इस पर भी है ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: अब दो सवाल? ...**(व्यवधान)**...

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: जिसका जवाब नहीं मिला, उसका भी जवाब माँग लूँ मंत्री जी से ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please don't argue. Ask the question ...*(Interruptions)*...

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: मेरे प्रश्न का जवाब मिले तब न ...**(व्यवधान)**... मेरे क्वैश्चन का जवाब ही नहीं दिया उन्होंने ...**(व्यवधान)**... मेरे दोनों क्वैचंस का जवाब नहीं दिया ...**(व्यवधान)**... आप जवाब दिलवा दीजिए ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Precious minutes are being lost. Please, put the question ...*(Interruptions)*...

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: माननीय सभापति जी, मुझे मेरे सवाल का उत्तर नहीं मिला ...**(व्यवधान)**... मैं क्या करूं?

MR. CHAIRMAN: Please, let the question be asked ...*(Interruptions)*... Why don't you just let the ...*(Interruptions)*... Please, ask your supplementary question ...*(Interruptions)*...

DR. MANMOHAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, that the pollution of our river systems is a matter of serious concern, I think, there cannot be two opinions about it. Having said that, I would also like to mention that water is a State subject and the bulk of the activity has to be in the State sector. The Central Government can offer assistance. We have schemes. As the hon. Minister has mentioned, the Central Government is willing and has been active in supporting and supplementing the efforts of the State Governments, and according to the information, that is available about the Ganga system after the Ganga Action Plan, there is some improvement, but I will be the last one to say that we are satisfied with the status.

श्री सभापतिः श्री नन्द किशोर यादव।

श्री प्यारे लाल खंडेलवालः महोदय, मेरा दूसरा सवाल है।

श्री सभापतिः आप के सवाल का जवाब हो गया।

श्री प्यारे लाल खंडेलवालः मेरा सेकंड सप्लीमेंटरी नहीं हुआ।

MR. CHAIRMAN: Mr. Khandelwal, you have already put two questions ...*(Interruptions)*...

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : वह मेरा पहला सवाल था।

MR. CHAIRMAN: Okay, put your question, but don't make a statement.

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक नई तकनीक आई है जो नदियों के पानी को शुद्ध कर सकती है। सुलभ इंटरनेशनल ने इस तकनीक को डवलप किया है। साथ ही और भी कुछ संस्थाएं होंगी ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Question please.

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : और भी संस्थाएं होंगी जिन्होंने नई तकनीक को डवलप किया होगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो नई तकनीक आई है और जिस से नदियों और दूसरे पानी को साफ किया जा सकता है, क्या सरकार उस नई टैक्नॉलोजी को अपनाकर नदियों के पानी को शुद्ध करने का प्रयत्न करेगी और उस की कोई योजना बनाएगी?

श्री नमो नारायण मीणाः सर, जहां तक नई तकनीकों का सवाल है, इस विषय में सारी दुनिया में अलग-अलग तकनीकें यूज होती रहती हैं। इस में depend करता है कि कहां, किस प्रकार की तकनीक काम में लाने लायक है, कहां उस में कितनी cost लगती है। ये सब options हमारे सामने रहते हैं, हम consultants को पूछते हैं, State concerned को पूछते हैं और सब कुछ देखकर हम ने यह किया है। माननीय सदस्य ने कहा है कि सुलभ इंटरनेशनल ने तकनीक डवलप की है, हम उस पर जरूर विचार करेंगे।

श्री सभापतिः श्री नन्द किशोर यादव।

श्री नन्द किशोर यादव: सभापति जी, गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल में कुल 433.32 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं यह देश नदियों का देश है। चाहे बड़ी नदी गंगा हो, जमुना हो, घाघरा हो, राप्ती हो-सभी में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने जो ये प्रांतों के आंकड़े दिए हैं, इतना पैसा खर्च करने के बाद, हम इस विषय में कितने सफल हो सके हैं या हम प्रदूषण कितना कम कर सके हैं? महोदय, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं कि जो सीवेज शोधन संयंत्र इन तीनों प्रांतों में लगे हैं, उन में से कितने काम कर रहे हैं और कितने बंद हो गए हैं, इस की माननीय मंत्री जी को जानकारी है या नहीं?

श्री नमो नारायण मीणा: सर, माननीय सदस्य ने पूछा है कि गंगा के पानी में कितना improvement हुआ है, उस बारे में हमारे सेंट्रल की चार इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सारे आंकड़ों को मॉनीटर करती हैं और उन की रिपोर्ट्स हमारे पास आती है। हम उन आंकड़ों के आधार पर यह कह सकते हैं कि 1986 में जब यह फर्स्ट चालू हुआ था और 2006 में क्या improvement हुआ है, मैं यह मानता हूं कि अभी भी एक स्ट्रेच है। कन्नौज डाउन स्ट्रीम और इलाहाबाद अप स्ट्रीम, इसके बीच का जो स्ट्रेच है, इसमें बीओडी लेवल डिजायर्ड लेवल पर नहीं आया, लेकिन पहले के मुकाबले में इम्प्रूवमेंट हुई है। इसकी हमने स्टडी भी करवाई थी और जो स्टडी करवाई थी, कोस्ट बेनेफिट एनालाइसेस जो स्टडी है, उसका जो रिजल्ट था, वह मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ - Thus in terms of both cost and time taken, GAP compares favourably with those of other major rivers ...*(Interruptions)*... तो इसके बारे में तो यह है। दूसरा उन्होंने जो प्रश्न उठाया है, तो जो इंडस्ट्रीज से पोल्युशन होता है, उसके लिए हमने इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाइ कर रखा है और उनमें कुछ के खिलाफ एक्शन लिया गया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री नन्द किशोर यादव: सर, हमने सीवेज के बारे में पूछा है कि जो संयंत्र लगे हैं, उनमें कितने काम कर रहे हैं?

MR. CHAIRMAN: Please let the hon. Minister proceed. ...*(Interruptions)*...

श्री नमो नारायण मीणा: सर, जो भी संयंत्र हैं, उनके लिए भारत सरकार स्टेट्स को वन टाइम असिस्टेंस देकर उनको प्रारंभ करा देती है और maintenance and opertaions is the responsibility of the State Government. मैं यह मानता हूँ ...**(व्यवधान)**...

श्री नन्द किशोर यादव: सर, मैं पूछ रहा हूँ कि आज ये कितने संयंत्र बंद पड़े हुए हैं? ...**(व्यवधान)**... मैं पूछ रहा हूँ कि कितने सीवेज संयंत्र बंद पड़े हैं?

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

श्री नमो नारायण मीणा: सर, as far as maintenance and operations is concerned, it is the responsibility of the State Government. माननीय सदस्य की यह बात मैं मानता हूँ कि बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस मामले में थोड़ी ढिलाई बरती है। कई जगहों पर इनकी मेंटीनेन्स सही है, मगर कहीं इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है, कहीं आदमी नहीं लगा

रखे हैं, जिसकी वजह से जितना इनका यूटीलाइजेशन होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ है। फिर भी हम बार-बार स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखते रहते हैं और इम्प्रूवमेंट कुछ हुआ है।

PROF. P.J. KURIEN: Mr. Chairman, Sir, in the southern most State Kerala, the only river taken up for cleaning is the river Pampa, on the bank of which is the famous Ayyappa Temple. Sir, even though the Pampa Action Plan for cleaning the pampa river had been announced a couple of years back, so far, it has not been implemented and it is progressing at a snail's pace. I would like to know from the hon. Minister what is the reason for the inordinate delay in implementing and completing this Pampa Action Plan. Will the Minister take steps to see that the project is implemented and completed as early as possible?

SHRI NAMO NARAIN MEENA: I have got the information with regard to Pampa river. We have approved certain projects of Pampa river amounting to Rs. 1,845 lakhs. The DPRs will be considered as and when the State Government sends them to us. I will let the hon. Member know the exact position..

SHRI MANOHAR JOSHI: Sir, I would like to say that no doubt the problem is with the State Governments. The hon. Prime Minister also mentioned. In our country, getting water or pure water should be a fundamental right. Sir, I really do not understand as to what is the difficulty for the Government in making a national policy on this issue. The question was asked but the reply has not been given. Why is the Government not declaring a national policy for making available the pure water to the people?

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Sir, as far as this question is concerned, there is a National River Conservation Authority under the chairmanship of the hon. Prime Minister, and, that is a policy formulation body. The hon. Prime Minister has asked me and other officers to prepare a strategy as to what should be done, how to revamp this entire system, and, what should be the approach. The approach should be holistic, The main reason is this. Sir, for the time being we are only improving the water quality. But, there is a need of quantity also. The minimum flow of river should be there. That is not there in the present situation. Therefore, I agree that there should be a policy. And, the agenda for the next meeting of the Authority will include review of river conservation strategy, institutional arrangement for a holistic programme, unlocking of potential human, technical, financial and independent monitoring. These things are going to be discussed in the coming meeting of the Authority which is going to be held under the Chairmanship of the hon. Prime Minister.

MR. CHAIRMAN: Question No. 244. ...*(Interruptions)*... Please, proceed with the Questions. ...*(Interruptions)*...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Sir, it is an important question and the river Ganga. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Every Starred Question is an important question. ...*(Interruptions)*... You can seek a discussion. ...*(Interruptions)*...

प्रो० राम देव भंडारी: सर, इस पर चर्चा करा दी जाए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI SITARAM YECHURY: May I request you, Sir, that as the Chairman, you may rule that there can be a Half-an-Hour discussion. ...*(Interruptions)*...

प्रो० रामदेव भंडारी : सर, इस पर half-an-hour डिस्कशन कर दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: It is always open to Members to seek a half-an-hour discussion. ...*(Interruptions)*... Please make a request. I assure you, you will get it. ...*(Interruptions)*...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: You don't allow a discussion here. ...(Interruptipons)... You don't allow me to raise a question. ...*(Interruptions)*... When I ask for a Half-an-Hour discussion, you don't allow ...*(Interruptions)*... What does it mean? ...*(Interruptions)*... Ganga is not a State river. ...*(Interruptions)*... It is a national river. ...*(Interruptions)*... One million people come.. .(Interruptions)..

MR. CHAIRMAN: I wish ...*(Interruptions)*... Please sit down. I can't hear whatever you are saying ...*(Interruptions)*... There are five voices coming from one side. ...*(Interruptions)*... I can't hear anything. ...*(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, we can have a half-an-hour discussion. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please, sit down. ...*(Interruptions)*... We will have a discussion. What is the difficulty? ...*(Interruptions)*... If you seek a discussion, it will be allowed. ...*(Interruptions)*... There are other questions also.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: The question is, my notice was accepted ...*(Interruptions)*... But, discussion is not being allowed. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: The Chair can only allow 'x' number of questions because there are other questions also. ...*(Interruptions)*... Please listen to me. ...*(Interruptions)*... Every question which is marked as a Starred Question is an important question. Every hon. Member who ask a question is a Member of this House. If there is some device or technology by which it is so decided that only one question will be discussed or only two questions will be discussed, please, write it in your rules of procedure and the Chair will follow it. But, my question simply is that there are other devices available. You can have a special discussion. You should use it. ...*(Interruptions)*...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Sir, but my objection is ...*(Interruptions)*...

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, it should go on record. He is making allegation. He is a senior Member. He can't do that. ...*(Interruptions)*... He is making a charge. He is a senior Member. He is a former Minister also. ...*(Interruptions)*...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: What is going on? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please, sit down. ...*(Interruptions)*...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: How the river is going ...*(Interruptions)*... What is the state of the colour of . ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please, sit down. ...*(Interruptions)*... Question No. 244. ...*(Interruptions)*...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: We want to have an assurance from the hon. Prime Minister. ...*(Interruptions)*...

'तिब्बत के ऊपरी इलाकों में बर्फ का पिघलना'

*244. **श्री जनेश्वर मिश्र:††**
श्री बृज भूषण तिवारी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि तिब्बत के ऊपरी इलाके में तेजी से बर्फ के पिघलने, हिम नदियों के सिमटने, घास के पीला पड़ने एवं नदियों के सूखते जाने से पर्यावरण को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभावों के बारे में कोई अध्ययन कराया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा है।

(क) इन्टरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की अप्रैल, 2007 में प्रकाशित वर्किंग ग्रुप-II रिपोर्ट के अनुसार, हिमालय के हिमनद विश्व के अन्य किसी भाग की अपेक्षा ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के अग्रणी वैज्ञानिकों के अनुसार, तिब्बत पठार के हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं। हिमनदों के पिघलने से अन्ततः और अधिक सूखा पड़ेगा, मरुस्थलीकरण का विस्तार और धूल भरे तूफानों में वृद्धि होगी। बर्फ के पिघलने से जल आपूर्ति में भी बाधा पहुचनें का खतरा है, क्योंकि कई नदियां हिमालय से निकलती हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Melting of ice in upper region of Tibet

*244. SHRI JANESHWAR MISHRA:††
SHRI BRIJ BHUSHAN TIWARI:

Will the Prime Minister be pleased to state:

(a) whether it is a fact that rapid melting of ice in upper region of Tibet, shrinking of glaciers, grass turning yellow and drying of rivers have posed a serious danger to the environment;

(b) if so, whether Government have conducted any study with regard to its adverse effect on the country; and

---

††सभा में यह प्रश्न श्री जनेश्वर मिश्र द्वारा पूछा गया।

†† The question was actually asked on the floor of the House by [Shri Janeshwar Mishra].